

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 572

बुधवार, 26 जून, 2019 / 5 आषाढ़, 1941 (शक)

देश में बेरोजगारी से संबंधित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आंकड़े

572. श्री संजय सिंह:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में बेरोजगारी से संबंधित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (आ.श.ब.स.) के आंकड़ों पर ध्यान दिया है;
- (ख) यदि हां, तो वर्ष 2014 से अब तक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आंकड़ों का राज्य-वार एवं वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ग) केन्द्र सरकार ने देश में गत 46 वर्षों में दर्ज सर्वाधिक बेरोजगारी से निपटने के लिए क्या उपाय किए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): जी हां। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) ने 2017-18 के दौरान आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) नामक एक नया नियमित रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण आरंभ किया है। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र के लिए सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) में पीएलएफएस की बेरोजगारी दर (यूआर) (प्रतिशत में) के प्राक्कलन अनुबंध में दिए गए हैं।

(ग): नियोजनीयता में उन्नति करने के साथ-साथ रोजगार सृजन सरकार का प्रमुख मुद्दा है। इसके अलावा, सरकार ने देश में रोजगार सृजन हेतु विभिन्न उपाय किए हैं जैसे अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना, भारी निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करना तथा विभिन्न स्कीमों पर सरकारी व्यय में बढ़ोतरी करना जैसे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा चालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एमजीएनआरईजीएस) एवं पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) स्कीम तथा आवास एवं शहरी प्रकाय मंत्रालय द्वारा चालित दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम)।

सरकार द्वारा मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया स्कीमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है तथा इनसे रोजगार की प्रकृति में उन्नति होने की संभावना है। सरकार द्वारा स्व-नियोजन को सुविधाजनक बनाने के लिए मुद्रा और स्टार्ट-अप स्कीमों आरंभ की गई हैं।

रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016-17 में प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना आरंभ की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत, सरकार ईपीएस और ईपीएफ के निमित्त सभी पात्र नए कर्मचारियों के लिए 01.04.2018 से नियोजक के संपूर्ण अंशदान (12% या जैसा स्वीकार्य हो) का भुगतान कर रही है तथा यह नए कर्मचारी के पंजीकरण की तारीख से अगले 3 वर्षों तक सभी क्षेत्रों के लिए लागू है।

सरकार ने राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) परियोजना का भी कार्यान्वयन किया है जिसमें एक डिजिटल पोर्टल होता है जो गतिशील, कुशल और प्रतिक्रियात्मक ढंग से नौकरी के सुमेलन हेतु नौकरी पाने वालों और नियोजकों के लिए एक राष्ट्र-व्यापी ऑनलाइन मंच उपलब्ध कराता है तथा इसमें कैरियर की विषय-सूची का भण्डार होता है।

दिनांक 26-06-2019 को उत्तर के लिए नियत राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 572 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में
संदर्भित विवरणी

प्रत्येक राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र के लिए सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के अनुसार बेरोजगारी दर (यूआर) (प्रतिशत में)									
राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	ग्रामीण			शहरी			ग्रामीण + शहरी		
	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
आंध्र प्रदेश	4.5	2.3	3.6	5.4	9.1	6.6	4.8	4.0	4.5
अरुणाचल प्रदेश	4.3	10.7	5.3	8.2	20.6	9.9	4.9	12.0	5.9
असम	7.4	14.3	8.3	5.3	11.4	6.3	7.2	13.9	8.1
बिहार	7.2	2.3	7.0	9.2	6.2	9.0	7.4	2.8	7.2
छत्तीसगढ़	2.7	2.1	2.5	5.9	11.4	7.5	3.3	3.3	3.3
दिल्ली	3.6	0.0	3.5	9.6	11.4	9.8	9.4	11.4	9.7
गोवा	10.7	21.0	13.9	6.0	29.8	13.8	8.1	26.0	13.9
गुजरात	5.5	4.0	5.2	4.3	4.3	4.3	5.0	4.1	4.8
हरियाणा	9.0	11.0	9.3	6.5	12.0	7.3	8.1	11.4	8.6
हिमाचल प्रदेश	6.2	3.9	5.2	7.4	13.7	8.7	6.4	4.3	5.5
जम्मू और कश्मीर	3.7	5.4	4.2	6.1	22.9	10.0	4.2	8.4	5.3
झारखंड	7.8	3.7	7.1	10.4	11.5	10.5	8.2	5.2	7.7
कर्नाटक	4.0	3.4	3.9	6.3	7.2	6.5	4.9	4.7	4.8
केरल	5.9	19.6	10.0	6.6	27.5	13.2	6.2	23.2	11.4
मध्य प्रदेश	4.5	1.2	3.6	7.9	6.9	7.7	5.3	2.1	4.5
महाराष्ट्र	3.5	2.8	3.3	6.2	11.5	7.4	4.7	5.4	4.9
मणिपुर	9.9	17.8	11.6	11.1	12.3	11.4	10.2	15.9	11.6
मेघालय	0.3	0.9	0.6	5.6	8.9	6.7	1.3	1.9	1.5
मिजोरम	5.9	8.3	6.5	12.7	17.7	14.4	8.8	13.3	10.1
नागालैंड	19.0	33.4	21.6	16.5	36.4	21.1	18.3	34.4	21.4
ओडिशा	7.4	5.3	6.9	7.3	12.7	8.3	7.3	6.3	7.1
पंजाब	7.4	10.3	7.8	6.5	13.5	7.7	7.0	11.7	7.8
राजस्थान	5.8	1.2	4.5	6.8	9.9	7.2	6.0	2.3	5.0
सिक्किम	2.0	3.9	2.7	4.2	9.9	5.8	2.6	5.2	3.5
तमिलनाडु	8.8	6.1	7.9	6.5	9.0	7.2	7.8	7.2	7.6
तेलंगाना	7.2	5.0	6.5	8.5	12.6	9.4	7.7	7.2	7.6
त्रिपुरा	6.1	7.9	6.3	6.0	19.7	8.7	6.1	11.6	6.8
उत्तराखंड	6.7	7.6	6.9	7.1	23.8	9.5	6.8	10.7	7.6
उत्तर प्रदेश	6.2	1.5	5.5	9.6	10.5	9.7	6.9	3.1	6.4
पश्चिम बंगाल	4.3	1.7	3.8	6.7	6.0	6.5	5.0	3.2	4.6
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	6.5	39.0	14.7	3.4	47.1	17.4	5.3	42.8	15.8
चंडीगढ़	3.9	1.3	3.5	5.2	21.2	9.2	5.2	20.8	9.0
दादरा और नगर हवेली	1.2	0.0	0.7	0.1	0.0	0.1	0.6	0.0	0.4
दमन और दीव	8.3	0.0	6.2	2.3	4.3	2.6	3.0	3.3	3.1
लक्षद्वीप	11.2	26.6	13.3	13.2	56.5	25.3	12.5	50.5	21.3
पुडुचेरी	5.8	37.3	10.4	8.0	17.6	10.3	7.2	21.7	10.3
अखिल भारतीय	5.8	3.8	5.3	7.1	10.8	7.8	6.2	5.7	6.1

स्रोत: राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण 2017-18.